प्रश्न– भारत में रक्षा खरीद नीति की समस्याओं को दूर करने के लिए रक्षा खरीद नीति-2016 प्रस्तुत की गई है, इसके तत्वों को स्पष्ट करें । क्या आपको लगता है कि यह भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगी? तथ्य सहित उत्तर दें। (200 शब्द)

Defence Procurement Policy 2016 has been presented to overcome the problems of Defence Procurement Policy in India. Explain its factors. Do you think that it will strengthen the India's Defence Sector? Answer with facts. (200 Words)

मॉडल उत्तर

भूमिका में रक्षा खरीद नीति को बतायें

प्रथम पैराग्राफ में रक्षा खरीद नीति की समस्या एवं नयी रक्षा खरीद नीति-2016 को दिखायें-

- देश में रक्षा उत्पादन मुख्यत: सरकारी कम्पनियों के हाथों में, शीर्ष पदों पर अफसरशाही का कब्जा।
- रक्षा उत्पादन में सरकारी कम्पनियों का एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा का अभाव।
- खरीद प्रक्रिया अधिक लम्बी, ऑफसेट प्रावधानों का स्पष्ट न होना।
- रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार एक सामान्य बात हैं।

नयी रक्षा खरीद नीति-2016

- नयी नीति में 'मेक इन इण्डिया' को बढ़ावा
- रक्षा खरीद में सर्वाधिक प्राथमिकता उन कम्पनियों को दी जायेगी जो स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण प्रकृति की होगी इस श्रेणी के उपकरणों में 40% सामान भारतीय होना चाहिये।
- खरीद नीति में ऑफसेट नियम में बदलाव, यदि विदेशी कम्पनी 2000 करोड़ रूपये से अधिक का रक्षा उपकरण भारत को बेचती है तो ही ऑफसेट नियम लागू होगा।
- इसके मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी तथा इसे 2 साल की समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा।
- निजी क्षेत्र में रक्षा उपकरणों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान विकास कोष तैयार किया जायेगा जिसमें भारत सरकार 90% योगदान करेगी।
- नयी रक्षा नीति में पर्याप्त पारदर्शिता के साथ एकल विक्रेता को भी शामिल किया गया है।
- बिचौलियों की भूमिका को देखते हुए एजेटंस के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया है, साथ ही रक्षा उद्योग में सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा सहायता दी जायेगी।

द्वितीय पैराग्राफ में सहमति के पक्ष में निम्न तथ्यों को लिखना है-

- रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इण्डिया' को बढ़ावा देने से अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी।
- निजी क्षेत्र का झुकाव रक्षा क्षेत्र की ओर होगा जैसे हाल ही में रिलांयस द्वारा नौसैन्य पोत का निर्माण।
- इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा पारदर्शिता बढ़ेगी तथा रक्षा उपकरणों की खरीद में तीव्रता आयेगी।
- निजी कम्पनी (रक्षा क्षेत्र) को रणनीतिक भागीदारी का दर्जा जिससे निजी कम्पनी को सरकारी कम्पनी के साथ जोड़ा जाएगा और हथियार बनाने में इनका सहयोग प्राप्त होगा।

अंत में संक्षिप्त एवं संतुलित निष्कर्ष दें (इसमें एक लाइन में यह भी दिखाये कि अभी और सुधार की आवश्यकता बताते हुए सकारात्मक निष्कर्ष)